



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367]
No. 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 1985/श्रावण 29, 1987
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 1985/SRAVANA 29, 1987

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

अधिसूचना
आय-कर

मा०का०नि० 665 (अ):—भारत सरकार और कीनिया सरकार ने आय पर दोहरे कराधान के परिजर्जन और करों के संबंध में राज वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए एक अभिसमय करने का, जैसा कि हम के उपबन्ध में उपबणित है निम्नवत् किया है :

और अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 की अपेक्षानुसार व सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं, जो उक्त अभिसमय की क्रमशः भारत और कीनिया में विधि का बल प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं;

और उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 की अपेक्षानुसार इस प्रभाव के राजनयिक लिपणों का, उक्त दोनों सरकारों के बीच आदान-प्रदान हो गया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्ध भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

[का०सं० 501/3/72-एफ. टी० डी०]

बी० व्हा० इराडी, संयुक्त सचिव

भारत और कीनिया के बीच दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन रोकने के लिए,

अभिसमय

भारत की सरकार तथा कीनिया गणराज्य की सरकार, दोहरे कराधान के परिहार के लिए और आय पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं।

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संबिदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक संबिदाकारी राज्य की ओर से आय पर लगाये जाने वाले करों पर लागू होगा, चाहे वे कर किसी भी तरह से लगाए जाते हों।

2. कुल आय, अथवा आय के तबों पर, जिसमें बल तथा अचल मंपत्ति के अन्तर्गत से हुए, अति लाभों पर लगाया जाने वाला कर शामिल है, लगे सभी करों को और उद्योगों द्वारा भेदा की गयी मजदूरी अथवा

वेतन को कुल राशि पर लपटे जाने करों को आय पर कर समझा जाएगा।

3. यह अभिसमय विषय रूप से जितने वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं:-

(क) भारत के मामले में आयकर, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत उस पर लगाया जाने वाला कोई भी अधिभार शामिल है, और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अतिकर (जिसे इनके पश्चात् "भारतीय कर" कहा गया है)

(ख) कानिया के मामले में :

आयकर अधिनियम (अनु. 470) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला आयकर (जिसे इसके पश्चात् "कानियाई कर" कहा गया है)।

4. यह अभिसमय आय पर किसी समरूप अथवा भारत जैसे ही करों पर भी लागू होगा, जो वर्तमान करों के अनुरिक्त अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् लगाये जाये। संविदाकारी राज्य, अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

साक्ष्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "कानिया" शब्द से अभिप्रेत है कानिया गणराज्य, जिसमें कानिया के प्रादेशिक समुद्र से बाहर, वह क्षेत्र भी शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, महाद्वीपीय तल सभा से संबंधित कानिया के कानूनों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है या किया जाए, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन के संबंध में कानिया सार्वभौम अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

(ख) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है, भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाशीय क्षेत्र तथा प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय तल-सीमा, विशिष्ट आर्थिक-क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 80) में उल्लिखित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के कतिपय अधिकार हैं और उस सीमा तक उनमें इन अधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, मानो वह समुद्री क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का ही एक अंग हो।

(ग) "संविदाकारी राज्य" और "अन्य संविदाकारी राज्य" शब्द से संदर्भ का अपेक्षा अनुसार कानिया अथवा भारत अभिप्रेत है।

(घ) "कर" शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, कानियाई कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें ऐसा कोई कर शामिल नहीं होगा, जो उन करों के संबंध में ऐसी सूक्ष्म अथवा भूल के संबंध में देय हो, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाये गए अर्थव्यवस्था के रूप में हैं।

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई एक व्यक्ति, कोई कंपनी और व्यक्तिगत या कोई भी ऐसा निकाय शामिल है जिन्हें कर के प्रयोजन से एक इकाई माना जाता है।

(च) "कंपनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अर्थात् कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जिसे कर के प्रयोजन से एक निगमित निकाय माना जाता है।

(छ) "कानियाई उद्यम" और "भारतीय उद्यम" शब्दों, से क्रमशः कानिया के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उद्यम अथवा उपक्रम और भारत के किसी निवासी द्वारा संचालित औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उद्यम अथवा उपक्रम अभिप्रेत है तथा "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा अनुसार, कोई कानियाई अथवा कोई भारतीय उद्यम अभिप्रेत है।

(ज) "राष्ट्रिक" शब्द से जैसा भी मामला हो, कानिया अथवा भारत की राष्ट्रियता धारण करने वाला कोई व्यक्ति तथा सभी विधिक व्यक्ति, सहभागिता और कानिया अथवा भारत में प्रचलित कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करने वाला संस्थापक, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है।

(झ) "मध्यम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है।

(क) कानिया के मामले में, बिन संवी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि।

(ख) भारत के मामले में, बिन मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

(ग) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द से अभिप्रेत है, एक संविदाकारी राज्य किसी उद्यम द्वारा संचालित जहाज या वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा, सिवाय ऐसी स्थिति में, जब यात्रा मात्र दूसरे संविदाकारी राज्य के अन्तर्गत स्थित स्थानों के बीच ही की गयी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य द्वारा, इस अभिसमय के उपबन्धों के प्रवर्तन में, किसी भी शब्द पद का जो अर्थवा यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं हो, वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

1. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिये "संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के कानूनों के अनुसार, अपने अधिवास, निवास, प्रसव के स्थान या इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगाये जाने योग्य है।

2. जहाँ, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी निवासीय हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जायेगी :-

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में एक निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (जिसे इसके पश्चात् "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" के रूप में उल्लेख किया जायेगा);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का निष्पत्ति नहीं किया जा सकता हो, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, अथवा यदि उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसमें वह स्वभावतः रहता हो;

(ग) यदि वह स्वाभावतः दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहना है, अथवा इसमें से किसी में भी नहीं रहना है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सख्त प्राधिकारी, पारस्परिक सहमति द्वारा, इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. अन्तर पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार कोई कंपनी दोनों ही संविदाकारी राज्यों की निवासी हो, तो यह मामला निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा :

(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जायेगा, जिसका वह राष्ट्रिक हो ;

(ख) यदि वह दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जायेगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

4. जहाँ एक व्यक्ति में भिन्न कोई व्यक्ति अथवा कोई कंपनी, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार, दोनों संविदाकारी राज्यों की निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य की निवासी मनी जायेगी, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अधिसूचन के प्रयोजनों के लिये, स्थायी संस्थापन शब्द-पद का अर्थ है, कारोबार का एक निश्चित स्थान, जहाँ पर उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2 "स्थायी संस्थापन" शब्द-पद में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) शाखा;

(ग) कार्यालय;

(घ) कारखाना,

(ङ) कार्यशाला;

(च) कोई खान, तेल का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) फर्म, बागान, अथवा ऐसा स्थान, जहाँ कृषि, वन संपत्ति, बागान अथवा उनसे संबंधित कार्य-कलाप किये जाते हैं ;

(ज) कोई भवन-स्थल, अथवा निर्माण अथवा ऐसी संयोजन परियोजना, जो छः महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती है ;

(झ) किसी भवन-निर्माण स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना पर छः महीने से अधिक समय के लिये पर्यवेक्षी गति-विधियों की व्यवस्था।

3. "स्थायी संस्थापन" शब्द में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा :—

(क) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;

(ख) उद्यम माल अथवा पण्यों के भण्डारण अथवा प्रदर्शन प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना;

(ग) अनन्य रूप से अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना ;

(घ) उद्यम के लिये माल अथवा पण्यों को केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना ;

(ङ) उद्यम के लिये, विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा उसी प्रकार के क्रिया-कलापों के लिये, जो प्रारंभिक अथवा सहायक किस्म के हों, अनन्य रूप से कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लिये अथवा उद्यम की ओर से, किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न हो और जिन पर पैराग्राफ 6 के उपबन्ध लागू होते हैं—प्रयोज्य राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जायेगा, यदि :—

(क) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिये अथवा उद्यम की ओर से संविदा संयोजन करने का प्राधिकार रखता है और सहज रूप से उसका प्रयोग करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिये माल अथवा पण्यों के क्रय तक हो सामित नहीं हों; और

(ख) वह उस प्रयोज्य राज्य में उस उद्यम के माल अथवा पण्यों का भण्डार रखता हो, जिनमें से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से अइसों को भूति करता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी भी उद्यम को, दूसरे संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन माना जायेगा, अगर वह किसी कर्मचारी के द्वारा अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि द्वारा, जो पैराग्राफ 6 के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं हो, उस दूसरे राज्य में बीमान-रिक्त बसूल करता हो अथवा उनमें जोखिमों का बीमा करता हो।

6. किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में, मात्र इस कारण से स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी बल्ल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जहाँ इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः किये जाते हों तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।

7. मात्र इस तथ्य से, कि कोई कंपनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य में निवासी हो, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में अपना कारोबार करती हो (किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा), इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरे कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय पर, जिसमें कृषि और वन-संपत्ति से आय भी शामिल है, कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जायेगा, जिसमें इस प्रकार की संपत्ति स्थित है।

2. इस अधिसूचन के प्रयोजन से "अचल संपत्ति" की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार की जायेगी, जिसमें विधाराधीन संपत्ति स्थित है। इस शब्द-पद में, किसी भी हालत में, अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वनविद्या में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर शामिल होंगे; ऐसे अधिकार, जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने का अधिकार और खनिज भण्डार खोदों और प्राकृतिक संसाधनों का कार्य अथवा काम करने के अधिकार के प्रतिपक्ष के रूप में पारस्परिक

अथवा नियत अवधियों के अधिकार; पोट, नौकाएं और बिमान अथवा संपत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अथवा संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, किराये देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर और संपत्ति की संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभों पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अथवा संपत्ति से होने वाली आय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिये प्रयुक्त अथवा संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जायेगा, जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न कर रहा हो। अगर वह उद्यम उपर लिखे अनुसार कारोबार कर रहा हो अथवा करता रहा हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है परन्तु केवल उतने ही अंश पर जो,

(क) उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों, (ख) उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथवा उसी प्रकार के मान्य अथवा पण्यों की बिक्री से प्राप्त हुए हों जैसे कि उस संस्थापन के माध्यम से किये जाते हैं अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे ही अथवा उसी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों के कारण प्राप्त हुए हों जैसे उन स्थायी संस्थापन के माध्यम से किये जाते हैं।

2. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उसका उस स्थायी संस्थापन के कारण उन लाभों का होना माना जायेगा, जिनके उसे इस स्थिति में, प्राप्त होने की अपेक्षा रहती, जब वह उन्हीं या वैसी ही परिस्थितियों में, उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और जिन उद्यम का वह स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता।

3. स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में व्ययों की उन कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन के लिये किये गये हों, और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यालयी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, बाहे वें उस राज्य में किये गये हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अत्यन्त।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उसके कानून के अनुसार उद्यम के कुल लाभों को, उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा शक्ति प्रभाजन पद्धति से कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी; तथापि प्रभाजन पद्धति ऐसी होनी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को उद्भूत होने वाले लाभों का कोई भी भाग मात्र इस आधार पर दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन को हुभा नहीं माना जायेगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस दूसरे राज्य में उद्यम के लिये माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जायेगा, जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका इस अधि-समय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इन अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

बिमान परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में बिमान संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायेगा, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध लाभों के उस अंश पर भी लागू होंगे, जो किसी संयुक्त बिमान परिवहन संचालन व्यवस्था अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में एकीकृत सेवा में भाग लेने से किसी संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में बिमान परिवहन से प्राप्त किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ अंतर्राष्ट्रीय यातायात में बिमान संचालन से प्रत्यक्ष संबंध निधियों पर व्याज इस प्रकार के बिमान संचालन से होने वाले आय मानी जावेगी और इस प्रकार के व्याज के संबंध में अनुच्छेद 12 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां इस प्रकार का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार के संचालन से लाभ प्राप्त करता है, वहां :-

(क) इस प्रकार के लाभ वह राशि समझी जायेगी, जो उद्यम द्वारा उस दूसरे राज्य में यहाँ परियहन अथवा माल वाहन के कारण प्राप्त सम्पूर्ण राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;

(ख) उस दूसरे राज्य में प्रभावी कर में से उसके 50 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती की जायेगी।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

जहाँ :-

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः एक संविदाकारी राज्य और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच, वाणिज्यिक अथवा किसी संबंधों में, ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां इस प्रकार के कोई लाभ, उन शर्तों के होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुए होते हैं किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे और तदनुसार उन पर कर लगाया जायेगा।

2. जहां से वे लाभ, जिन के लिये एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस, राज्य में कर लगा दिया गया है, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों में शामिल कर लिये जाते हैं और उन पर तब-नुसार कर लगाया जाता है, और इस प्रकार शामिल किये गये लाभ वे लाभ हैं, जो दूसरे राज्य के उस उद्यम का तब प्रोद्भूत हुए होते, यदि उद्यमों के मध्य लगाई गयी शर्तें वे होती, जो स्वतन्त्र उद्यमों के बीच लगाई जाती हैं, वहां वह प्रथमोल्लिखित राज्य उन लाभों पर, प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रभाविता कर की राशि का समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार का समायोजन निर्धारित करने में, लाभ के स्वरूप के संबंध में इस अधि-समय के अन्य उपबन्धों पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

अनुच्छेद - 11

लाभांश

1. किसी कंपनी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेषों अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावे नहीं हैं, और लाभों में सहयोगी हों, प्राप्त आय से तथा होकरों अथवा किसी अन्य मद से जिसे लाभांश समझा जाता है अथवा उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा, जिसकी कि वितरण करने वाली कंपनी निवासी है, किसी कंपनी के विभाजन से प्राप्त आय में सम्मिलित अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है।

4. पैराग्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, बड़ा स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाएँ संपन्न करता है, और जिस धारिता के कारण लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, जैसी भी स्थिति हो, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध लागू होंगे।

5. अहाँ ऐसी कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, बड़ा उस दूसरे राज्य द्वारा कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, जहाँ तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं, उसे छोड़कर अथवा जहाँ तक कि वह धारिता, जिसके संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है, उस राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के अधिनिरित लाभों पर अधिनिरित लाभों संबंधी कर लगाया जाएगा, बल्कि अदा किए गये लाभांश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह अर्जित होता है किन्तु जिस संविदाकारी राज्य में व्याज अर्जित होता है, उसमें इस प्रकार प्रभावित कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार का अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण को, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सेंट्रल बैंक अथवा उस सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी को प्रत्येक व्याज पर प्रथमालिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट दी जाएगी। संविदाकारी राज्यों के सशम प्राधिकारों,

परस्पर सहमति से कोई भी अन्य सरकारी संस्थान निर्धारित कर सकते हैं, जिस पर यह पैराग्राफ लागू होगा।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द में सरकारी प्रति-भूतियों, वध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों बाह्य वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं, और चाहे वे लाभों में भागी होने का अधिकार रखते हों अथवा नहीं और हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय और गाय हो लाभ अन्य ऐसी आय से अभिप्राय है जो, जिस संविदाकारी राज्य में आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिए गए धन में प्राप्त आय में समाविष्ट की गयी हो।

5. पैराग्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज प्राप्तकर्ता, संविदाकारी राज्य का निवासी होने में, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता हो जिसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्याज उत्पन्न हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाएँ निष्पन्न करता हो, और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राज-नीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, बाढ़े वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में नाई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार है, जिसके संबंध में वह ऋण किया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।

7. अहाँ, व्याज अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विविध प्रकार का संबंध होने के कारण अदा किए गये व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उसे अदा किया गया है, उस रकम में बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अधिनिरित भाग पर इस अभियमय के अन्य उप-बंधों का अनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

रायटियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायटियाँ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु ऐसी रायटियों पर, उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं। किन्तु जिस संविदाकारी राज्य में रायटियाँ उद्भूत होती हैं उस में इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायटियों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायटियाँ" शब्द में साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिसमें चलचित्र फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें भी शामिल हैं), कोई

पेटेंट, व्यापार-चिह्न, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुण फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकूल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उत्स्कार के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टी का प्राप्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाया है अथवा उस दूसरे राज्यों में, वहां पर स्थित एक निश्चित आधार से व्यावसायिक सेवाओं करता है, तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के बारे में रायल्टियों की अदायगी की जाती है, वह उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब रायल्टी अदा करने वाला स्वयं कोई संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार है जिसके संबंध में रायल्टी अदा करने की देनदारी ली गयी थी, और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा, उद्भूत हुई हैं तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।

6. जहां, रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, अधिकार प्रदान नुस्खा की धार में रहने द्वारा, जिसके लिए वे रायल्टियों अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंत में उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में अदा की गयी रकमों के अधिक भाग पर, इस अभिसमय के श्रेय उपबंधों का अनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूँजीगत अभिलाभ

1. अबल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले अभिलाभ, जैसे कि अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिभाषित हैं, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हों सकेंगे जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. ऐसी चल संपत्ति के हस्तांतरण से, जो इस स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो आ एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति का भाग हो, प्राप्त अभिलाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्वाम के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेंगे।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जलपौतों तथा वायुयानों के हस्तांतरण से जिन्हें ऐसा उद्यम अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अंतर्गत परिचालित करता है तथा इन प्रकार के जलपौतों तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के मान लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

(क) किसी ऐसी कंपनी के धारकों जिसकी संपत्ति में एक संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अबल संपत्ति शामिल हो और

(ख) किसी भागीदारी अथवा किसी न्याम में हित जिसकी संपत्ति में एक संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अबल संपत्ति शामिल हो, के हस्तांतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लग सकेंगे। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ "अबल संपत्ति" शब्द-पद में, उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी कंपनी के शेयर अथवा उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित किसी भागीदारी अथवा किसी न्याम में हित शामिल है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

अनुच्छेद 15

प्रबंध-व्यवस्था तथा व्यावसायिक फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की जाने वाली प्रबंध व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस पर कर, उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जा सकेगा जिसमें ये उद्भूत होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाए जाने वाले कर की रकम, प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस की सकल रकम के $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस" शब्दों का अर्थ, अदायगी करने वाले व्यक्ति से इतर अन्य व्यक्तियों को प्रबंधकीय, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा परामर्शी किस्म की किन्हीं सेवाओं के प्रतिकूल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अदायगी है।

4. पैराग्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस उद्भूत होती है, कोई ऐसा स्थायी संस्थापन हो जिससे वे सेवाएं कराए गए हों जिन के कारण प्रबंध व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस उद्भूत होती हो; ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

5. प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई तब मानी जाएंगी जबकि अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य हो, कोई राजनीतिक उपमंडल हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां प्रबंध व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है जिसके संबंध में प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस अदा करने की देनदारी ली गयी थी और ऐसी प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन द्वारा बहन की जाती है, तो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।

6. जहां अदा करने वाले तथा प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस के लाभप्रद स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस की अदा की गयी रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए फीस की अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले तथा लाभप्रद स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंत में उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। उस स्थिति में, अदा की गयी रकमों के अधिक भाग पर, उस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 19

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृत्ति-संबंधी सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि—

- (क) अपने कार्य-कलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान पर नियमित रूप से उपलब्ध न हो, जिस मामले में उस दूसरे राज्य में कर उतनी रकम पर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो; अथवा
- (ख) कीनिया के मामले में सम्बद्ध कैलेण्डर वर्ष में अथवा भारत के मामले में सम्बद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए अपने कार्यकलापों के प्रयोजन के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित नहीं रहा हो और ऐसी स्थिति में उस राज्य में आय की उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किए गए कार्यकलापों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।

2. "वृत्ति-संबंधी सेवाएं" शब्द-जट में स्वतंत्र वैज्ञानिक साहित्यिक, कलात्मक शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, दकियों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल है।

अनुच्छेद 17

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त घेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा जब कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथमोक्त राज्य में ही लगेगा, यदि :—

- (क) प्राप्तकर्ता सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में उस अवधि अथवा उन अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं हों, और
- (ख) पारिश्रमिक की अवायवी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में कलपोन पर अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था है।

अनुच्छेद 18

निदेशकों की फॉस

एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैमियन में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का

निवासी है, प्राप्त निदेशक की फॉस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 19

कलाकार तथा खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 16 तथा 17 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं, जैसे थियेटर, चषचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकारों तथा संगीतकारों और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किए गए हों।

2. इस अभिसमय में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां एक संविदाकारी राज्य में, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी लोक मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी की सेवाओं की व्यवस्था दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा की जाती है, जहां उन सेवाओं की व्यवस्था करने से उक्त उद्यम को प्राप्त लाभों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लोक मनोरंजनकर्ताओं तथा खिलाड़ियों की सेवाओं पर लागू नहीं होंगे, यदि एक संविदाकारी राज्य की उनकी यात्रा का ध्येय पूर्णतः अथवा प्रयत्नितः दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों में बहन किया जाता हो।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-मंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, उस राज्य अथवा उसके उप-मंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा किया गया, पेंशन में भिन्न, पारिश्रमिक, केवल उस राज्य में ही कराधेय होगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में, जिसका कि प्राप्तकर्ता निवासी है, कर लगेगा यदि उस राज्य में सेवाएं की जाती हैं और प्राप्तकर्ता मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय अथवा कारोबार के संबंध में की गयी सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 21

पेंशन

1. एक संविदाकारी राज्य के स्रोतों में किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त की जा रही किसी भी पेंशन (इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित किसी भी पेंशन से भिन्न) तथा किसी भी वार्षिकी पर कर वाला प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकता है, लेकिन यदि व्यष्टि पर, पेंशन अथवा वार्षिकी के संबंध में, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा :—

(क) पेंशन अथवा वार्षिकी का 5 प्रतिशत, अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में पेंशन अथवा वार्षिकी पर प्रभावी कर की रकम।

2. एक संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उस राज्य द्वारा निमित्त निधियों में से किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य के सरकारी कार्यों

को करने के लिए को गयी सेवाओं के लिए बड़ा की जाने वाली गैशन पर कर उसी संविदाकारी राज्य में लग सकेगा।

3. "वापसी" शब्द का अर्थ उग उल्लिखित राशि में है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिये, अदायगिया करने के पिछो दायित्व के अर्धान, जीवन पर्यन्त अथवा विनिश्चित अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 22

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मास अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गयी अदायगियों पर, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट होगी।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा विग गग प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा माधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में लगातार तीन वर्षों में अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 23

प्राध्यापक तथा अध्यापक

1. एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो उस संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन अथवा शोधकार्य के प्रयोजनार्थ एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए एक संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, और जो ऐसा दौरा करने से तत्काल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिधमिक पर, जिनके संबंध में उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगना है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी। तथापि, उस राज्य में बाहर के स्त्रोतों से ऐसे कार्य के लिए प्राप्त कोई भी पारिधमिक, प्रथमोल्लिखित राज्य में कटौती योग्य नहीं होगा।

2. यह अनुच्छेद उस शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मूलतः विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 24

आय जिनका स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया गया

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उस मदों पर, जिन्हें इस अधिनियम के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, जिनके संबंध में उस पर उस राज्य में कर लगना है, केवल उसी राज्य में ही कर लगेगा।

2. तथापि, यदि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्त्रोतों से ऐसी आय प्राप्त की जाती है तो ऐसी आय पर उस राज्य में भी जिसमें वह उद्भूत होती है, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान के उपाकरण के लिए प्रणाली

1. जिन मामलों में इस अधिनियम में विपरीत प्रावधान बनाए जाते हैं, उन्हें छोड़कर, दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शामिल करने रहेंगे।

2. (क) कीनिया के कानूनों के अंतर्गत और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यदि भारत के किसी निवासी की कीनिया में स्थित साधनों में प्राप्त आय पर, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा भारत और कीनिया दोनों में कर लगाया गया है, तो कीनिया के कर की देय रकम को, उक्त आय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथा संगणित) भारतीय कर की उक्त रकम से अधिक नहीं हो, जो कीनिया में स्थित साधनों में प्राप्त आय के अनुसार हो, लेकिन जहां ऐसा निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में द्रष्टिकर बड़ा करना है, वहां उपर्युक्त जमा रकम प्रथम बार कंपनी द्वारा भारत में आयकर के प्रति देय मानी जाएगी, और शेष रकम, यदि कोई हो, तो वह उसके द्वारा भारत में अदा किया जाने वाले अधिकार के रूप में जमा मानी जाएगी।

(ख) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए, "कीनिया का देय कर" शब्दों में निम्नलिखित को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल नहीं मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए कीनिया के कर के रूप में देय रही हो :—

(1) आय कर अधिनियम 1973 की द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ 24 के अधीन मंजूर की गयी कोई पूंजी-निवेश कटौती;

(2) आयकर की निम्नतर निगम दर जिसकी आय कर अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची के पैराग्राफ 2 (ख) में व्यवस्था है;

(3) अन्य कोई भी उपबंध जिन्हें आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए बाद में कर की किसी छूट अथवा कटौती को मंजूर करने के लिए अधिनियमित किया गया हो और जिनके लिए संविदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारों सहमत हो।

3. (क) भारत के कानूनों के अंतर्गत, और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, प्रत्यक्ष अथवा कटौती द्वारा कीनिया के किसी निवासी की भारत में स्थित साधनों में प्राप्त आय पर, भारत और कीनिया दोनों में कर लगाया गया है तो भारतीय कर की देय रकम को, उक्त आय के संबंध में देय कीनिया के कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि जमा की रकम (ऐसी जमा स्वीकृत किए जाने से पूर्व यथा संगणित) कीनिया के कर की उक्त रकम से अधिक नहीं हो, जो भारत में स्थित साधनों में प्राप्त आय के अनुसार है;

(ख) उपर उपपैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए, "देय भारतीय कर" शब्दों में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गयी मान ली जाएगी जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1964, की निम्नलिखित धाराओं में निर्धारित किए गए विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसार भारतीय कर बटा दिया गया है :—

(क) धारा 10(4), 10(4क), 10(6) (7क), 10(15) (4), 10क, 32क, 33क, 35क, 35ग, 80अ, 80अ, 80, और 80ड

(ख) कोई भी अन्य उपबंध, जो कराधेय आय से कटौती करने अथवा कर की छूट अथवा कमी प्रदान करने के लिए बाद में अधिनियमित किए जाएं, जिनके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच यह सहमति हो कि वे आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए हैं।

4. जहाँ इस अभिसमय के अंतर्गत एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त भाग के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, सब प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की गैर भाग पर कर संगणना करने में कर की बड़ी दर लागू कर सकता है जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट दी गयी भाग को छूट न दिए जाने की स्थिति में लागू होती है।

अनुच्छेद 26

सम व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही स्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य में प्रयुक्त उद्यमों पर लगाया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, नागरिक हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूटें, राहतें और कटौतियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णता अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द-पद का अर्थ ये कर हैं जो इस अभिसमय का विषय हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के होते हुए भी, भारत की निवासी किसी कंपनी पर, जिसका कीनिया में स्थायी प्रतिष्ठान है, कीनियाई कानून के उपबंधों के अनुसार कर की अतिरिक्त दर लागू रहेगी, किन्तु यह अतिरिक्त दर 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, ऐसी कंपनी पर ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य में वैसे ही उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है। यह मामला ऐसी कार्यवाही अथवा ऐसी कार्यवाहियों में से अस्तंत कार्यवाही, जैसा भी मामला हो की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

673 GI/85—2

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिवर्तन की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उक्त मामले का हल करने का प्रयास करेगा। किन्तु, यदि किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई अथवा संकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. इस अभिसमय के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे-वृष्ट व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने में जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय को कार्यवाहित करने के लिए अथवा इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में छल-कपट अथवा राजस्व अपव्यय को रोकने के लिए आवश्यक हो, जहां तक कि उनके अधीन कराधान-व्यवस्था इस अभिसमय के अनुरूप हो। इस प्रकार आदान-प्रदान की गयी किसी भी सूचना को गुप्त समझा जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को प्रकट नहीं किया जाएगा जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली से संबंधित न हों, जो कि इस अभिसमय के विषय हैं।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाहिर आलना नहीं होगा :

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे विवरण देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकते हों;
- (ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो और जिसकी प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 29

राजनयिक तथा कौमली कार्य

इस अभिसमय में निहित किसी व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौमली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

1. यह अभिसमय उस तारीख से लागू होगा, जब भारत में तथा कीनिया में वे सभी बातें पूरी कर ली जाएँगी जो इस अभिसमय को प्रमथः भारत में तथा कीनिया में कानून की शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

2. दोनों संधिदाकारी राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अपक्षाओं के पुरा हो जाने के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान, जिनमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह प्रवेष्टा पूरी कर ली गयी है, नई दिल्ली में किया जाएगा।

3. ऐसी राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान हो जाने पर यह अभिसमय :

(क) कीनिया में :

(i) जिस वर्ष में सभी अवैधित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को या उसके बाद गैर रिहायशियों को भ्रष्टा की गयी या उनके हिसाब में जमा दिखाई गयी रकमों पर खोन पर रोके गए कर के संबंध में।

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में सभी अवैधित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं उस वर्ष में 1 जनवरी को या उसके बाद प्रारम्भ होने वाले आय वर्ष के लिए उद्भूत होने वाले आय पर अन्य करों के संबंध में।

(ख) भारत में, जिस वर्ष में सभी अवैधित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं उस वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अवस्था उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में।

अनुच्छेद 3।

समाप्ति

यह समय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा परन्तु कोई भी संधिदाकारी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसवें दिन को अवस्था उससे पहले दूसरे संधिदाकारी राज्य को, राजनयिक माध्यमों से, समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति में यह अभिसमय :

(क) कीनिया में :

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अवस्था उसके बाद गैर-रिहायशियों को भ्रष्टा की गयी अवस्था उनके हिसाब में जमा दिखाई गई रकमों पर खोन पर रोके गये कर के संबंध में;

(ii) जिस आय-वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो उसके अगले परवर्ती वर्ष में तथा साथ के वर्षों में उद्भूत होने वाली आय पर अन्य कर के संबंध में;

(ख) भारत में :

जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कैलेंडर वर्ष में और परवर्ती वर्षों में, अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में लागू नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए अधिष्ठान्त प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।

नैरोबी में आज वर्ष एक हजार तीसो पचासी के अप्रैल मास के 12 दिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, परन्तु किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

ह /-

भारत गणराज्य
की सरकार की
ओर से

ह /-

कीनिया- गणराज्य
की सरकार की
ओर से

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th August, 1985

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 665(F).—Whereas the Government of India and the Government of Kenya have concluded a Convention, as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

And whereas all the requirements have been completed in India and Kenya as are necessary to give the said Convention the force of law in India and Kenya respectively, as required by paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

And whereas the diplomatic notes to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by paragraph 2 of Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

[F. No. 501/3/72-FTD]

V. U. ERADI, Jt. Secy.

CONVENTION BETWEEN INDIA AND KENYA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of India and the Government of the Republic of Kenya desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income have agreed upon the following measures:

ARTICLE 1 PERSONNEL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2 TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) in the case of India: the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) (hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) in the case of Kenya :

the income taxes imposed under the Income Tax Act (Cap. 70) (hereinafter referred to as "Kenyan Tax").

4. This Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws,

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention unless the context otherwise requires:

(a) The term "Kenya" means the Republic of Kenya, including any area outside the territorial waters of Kenya which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Kenya concerning the Continental Shelf, as an area over which Kenya may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources;

(b) The term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Kenya or India as the context requires;

(d) the term "tax" means Kenyan tax or Indian tax as the context requires, but shall not include any tax which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;

(e) the term "person" means an individual, a company and any other body of persons treated as an entity for tax purposes;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "Kenyan enterprise" and "Indian enterprise" mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Kenya and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of India and the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean a Kenyan enterprise or an Indian enterprise, as the context requires;

(h) the term "national" means any individual possessing the nationality of Kenya or India as the case may be and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Kenya or India, as the case may be.

(i) the term "competent authority" means:

(a) in the case of Kenya, the Minister of Finance or his authorised representative;

(b) In the case of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(j) the term "international traffic" means any voyage of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting state, except where the voyage is confined solely to places within the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this convention by a Contracting State any terms not otherwise defined herein shall unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the present Convention.

ARTICLE 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purpose of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence place of management or any other criterion of a similar nature.

2. There by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status shall be determined in accordance with the following rules:—

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");

(b) if the Contracting State in which he has his Centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the Competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) it shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which it is a national ;
- (b) if it is a national of neither of the Contracting States then it shall be deemed to be a resident of a Contracting State in which its place of effective management is situated.

4. Whereby reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, it shall then be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, oilwell, quarry or other place of extraction of natural resources ;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural forestry, plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months ;
- (i) the provision of supervisory activities for more than six months on a building site or construction or assembly project.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise ;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply—shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if :

- (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ; or
- (b) he maintains in that first mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfils orders on behalf of that enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks therein through an employee or through a representative who is not an agent of independent status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company, a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property including income from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. For the purposes of this Convention, the term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, right to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property and to profits from the alienation of such property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to: (a) that permanent establishment, (b) sales in the other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to the permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State, according to its law, to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No portion of any profits arising to an enterprise of a Contracting State shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Contracting State by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other State for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of the profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

3. For the purposes of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

ARTICLE 9

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State:

Provided that where such an enterprise derives profits from such operation in the other Contracting State:

- (a) such profits shall be deemed to be an amount not exceeding five per cent of the full amount received by the enterprise on account of the carriage of passengers or freight embarked in that other State;
- (b) the tax chargeable in that other State shall be reduced by an amount equal to fifty per cent thereof.

ARTICLE 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their, commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State, if the conditions made between the enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. In determining such an adjustment due regard shall be had to the other provisions of this Convention in relation to the nature of the income.

ARTICLE 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged in the Contracting State in which the interest arises shall, not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority, shall be exempt from tax of the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting State may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other incomes assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment

or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and that interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount, in that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged in the Contracting State in which the royalties arise shall, not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed-base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such

royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 14

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of—

- (a) shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, and
- (b) interest in a partnership or a trust, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State,

may be taxed in that State. For the purposes of this paragraph the term "immovable property" includes the shares of a company referred to in subparagraph (a) or an interest in a partnership or a trust referred to in subparagraph (b).

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in that State.

ARTICLE 15

MANAGEMENT AND PROFESSIONAL FEES

1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such management or professional fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 17½ per cent of the gross amount of the management or professional fees.

3. The term "management or professional fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical, professional or consultancy nature.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the management or professional fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the management or professional fees are effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the management or professional fees was incurred and such management or professional fees are borne by such permanent establishment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner of the management or professional fees or between both of them and some other person, the amount of the management or professional fees paid, having regard to the service for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities

for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned in the case of Kenya or the previous year concerned in the case of India, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.

ARTICLE 17

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in the other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 18

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 19

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 16 and 17, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television

artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised.

2. Notwithstanding anything contained in this Convention, where the services of public entertainer or an athlete mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived by that enterprise from providing those services may be taxed in the first mentioned State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to services of public entertainers and athletes. If their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State.

ARTICLE 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident if the services are rendered in that State and the recipient did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 21

PENSIONS

1. Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (2) of this Article) and any annuity, derived from sources within a Contracting State by an individual who is a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State, but if the individual is subject to tax in the other Contracting State in respect of the pension or annuity the tax so charged in the first-mentioned Contracting State shall not exceed the lower of—

- (a) 5 per cent of the pension or annuity; or
- (b) the amount of tax chargeable on the pension or annuity in the other Contracting State.

2. Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State to an individual for services rendered to that Contracting State in the discharge of governmental functions may be taxed only in that Contracting State.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for ade-

quate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 22

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years.

ARTICLE 23

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding one year for the purpose of teaching or conducting research at a University, College, School or other Educational Institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State. However, any remuneration for such work received from sources outside the State shall not be deductible in the first-mentioned State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 24

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

1. Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing articles of this Convention in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State.

ARTICLE 25

METHOD OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. (a) The amount of Kenyan tax payable, under the laws of Kenya and in accordance with the provision of this Convention, whether directly or by deduc-

tion, by a resident of India, in respect of income from sources within Kenya which has been subjected to tax both in India and in Kenya, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income, provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the income derived from sources within Kenya; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income-tax payable by the company in India, and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Kenyan tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Kenyan tax for any year but for : (i) any investment deduction granted under paragraph 24 of the Second Schedule to the Income-tax Act, cap 470; (ii) the lower Corporation rate of income-tax provided by paragraph 2(b) of the Third Schedule to the Income-tax Act, cap 470; (iii) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Kenya, in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Kenya, shall be allowed as a credit against Kenyan tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Kenyan tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the income derived from sources within India;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following Sections of the Income-tax Act, 1961 : -

(a) Sections 10(4), 10(4A), 10(6) (vii), 10(15)(iv), 10A, 32A, 33A, 35B, 35CC, 80HH, 80I, 80K, 80L, and

(b) any other provisions which may subsequently be enacted granting a deduction from taxable income or exemption from or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax in the remaining income of that person apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

ARTICLE 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

6. Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraphs, a company which is a resident of India and which has a permanent establishment in Kenya shall remain subject to an additional rate of tax in accordance with the provisions of Kenyan law, but such additional rate shall not exceed 7.5 per cent. However, such a company will not be subjected to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

ARTICLE 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the State of which he is a resident. The case must be presented within three years of the date of such action or the latest of such actions as the case may be.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention. Any agreement

reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may Communicate directly with each other for the purposes of applying the provisions of this Convention. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the contracting States

ARTICLE 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention or for preventing fraud or fiscal evasion concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation there-under is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation.

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, Commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privilege of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall come into force on the date when the last of all such things shall have been done in India and Kenya as are necessary to give the Convention the force of law in India and Kenya respectively.

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in

paragraph 1 of this Article. The exchange of diplomatic notes certifying that this requirement has been completed shall take place at.....

3. Upon the exchange of such diplomatic notes, this Convention shall have effect :

(a) in Kenya;

- (i) In respect of taxes withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after 1st January in the calendar year following the year in which all the required formalities are completed.
- (ii) In respect of other taxes on income arising for the year of income commencing on or after the 1st January in the calendar year in which all the required formalities are completed.

(b) In India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after 1st day of April, in the year in which all the required formalities are completed.

ARTICLE 31

TERMINATION

This Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect.

(a) In Kenya :

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the 1st day of January in the calendar next following that in which the notice is given;
- (ii) in respect of other tax on income arising for the year of income next following that in which the notice of termination is given, and subsequent years;

(b) in India:

in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Nairobi this twelfth day of April one thousand Nine Hundred and Eightyfive in the English, and Hindi languages but in the event of any dispute, the English text shall prevail.

Sd/-

Sd/-

For the Government of the
Republic of Kenya

For the Government of the
Republic of India

